दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अक्तूबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **5**

- आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना 5
- नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टॉवर 6
- मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में टोरेंट गैस के सिटी गैस स्टेशन का उद्घाटन किया 6
- मुख्यमंत्री ने पुस्तक 'सावरकर-एक भूले-बिसरे अतीत की गूंज' का विमोचन किया 7
- वन्यजीव सप्ताह 2021 का शुभारंभ 7
- उत्तर प्रदेश के सात रेलवे स्टेशन होंगे ईको-स्मार्ट 7
- उत्तराखंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 3 महीने के लिये बढ़ाया 8
- डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी 8
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 8
- उत्तर प्रदेश में निर्मित 'वेबली स्कॉट' बाज़ार में हुआ लॉन्च 9
- उत्तराखंड में क्षेत्रीय उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ 9
- उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ 10
- प्रदेश के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन 10
- जस्टिस राजेश बिंदल 11

नोट :

- डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 11
- उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप 11
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति 12
- नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप-10 में से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले 12
- 'खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो-2021' 12
- विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान 13
- कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 14
- मुख्यमंत्री ने की पुलिस शहीदों की पोषाहार भत्ता बढ़ाने की घोषणा 14
- उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत 15
- फैज़ाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन 15
- उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण 16
- 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना' का शुभारंभ 16
- मुख्यमंत्री ने गोंडा में 1,132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया 16
- उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के चार सदस्यों ने ली शपथ 17
- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2021 17
- उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति, 2021 18
- सोरों सुकर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित 18
- उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति, 2021 19

नोट :

दृष्टि
The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना

चर्चा में क्यों ?

- 30 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के मिशन के तहत 'आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना' शुरू की। इस योजना के तहत 2,725 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन किया जाएगा, जिससे 27.25 लाख शेयरधारक किसानों को सीधे लाभ होगा।

प्रमुख बिंदु

- कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिये प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक FPO स्थापित करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपए निर्धारित किये हैं।
- कृषि विभाग ने आगे कहा कि सरकार अगले पाँच वर्षों के लिये प्रति वर्ष 625 FPO स्थापित करेगी। केंद्र सरकार के संस्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (DASP), हॉर्टिकल्चर फेडरेशन, योग्य FPO और स्वैच्छिक संगठन FPO के गठन के लिये मिलकर काम करेंगे। प्रत्येक FPO से औसतन 1.5 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।
- 722.85 करोड़ रुपए की इस योजना से अगले पाँच वर्षों में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) से जुड़े 27 लाख से अधिक किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- वर्तमान में प्रदेश के कुल 824 प्रखंडों में से 408 प्रखंडों में कुल 693 FPO का गठन किया गया है। औसतन लगभग 500 से 1,000 किसान FPO से जुड़े हैं।
- FPO के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। योजना के तहत राज्य में कार्यरत् FPO से जुड़े किसानों को 5 लाख रुपए के ऋण पर चार प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार कृषि विकास से जुड़ी संस्थाएँ कृषि के बुनियादी ढाँचे को विकसित करके खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सक्षम होंगी।
- योजना के तहत क्लस्टर आधारित कारोबारी संगठनों को पाँच वर्षों के लिये FPO बनाने हेतु पाँच लाख रुपए और नवगठित FPO को तीन साल के लिये छह लाख रुपए सालाना का कर्ज़ दिया जाएगा।
- फसल कटाई के बाद की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिये FPO को तीन प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे FPO से जुड़े कम-से-कम 500 से 1,000 किसानों को लाभ होगा और प्रत्येक वर्ष 3,000 नौकरियों का सृजन भी होगा।
- गौरतलब है कि अभी तक राज्य में उर्वरक, बीज एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाली कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) मार्जिन मनी के अभाव में कृषि अधोसंरचना कोष (AIF) की योजना का लाभ नहीं उठा पा रही थीं। अब राज्य के 1,500 PACS इस योजना से किसानों को लाभान्वित कर सकेंगी।
- साथ ही सस्ते कर्ज़ की उपलब्धता से राज्य की प्रत्येक PACS 20 लाख रुपए की परियोजना शुरू कर सकेंगी। PACS के ऐसे प्रोजेक्ट में राज्य सरकार 4 लाख रुपए मार्जिन मनी के तौर पर देगी, जबकि AIF 16 लाख रुपए देगी। इसकी ब्याज दर एक फीसदी होगी।
- इस पैसे से PACS गोदाम बना सकेंगे, जिससे किसानों को लंबे समय तक अपनी उपज के भंडारण में मदद मिलेगी। साथ ही कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 27 मंडियों में कटाई उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन अधोसंरचना के निर्माण के लिये 140 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। मंडी परिषद भी AIF से महज़ 3 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज़ लेकर संसाधन बढ़ा सकेगी।

नोट :

नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टॉवर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की मदद से डीएनडी एक्सप्रेसवे पर वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर (एपीसीटी) को स्थापित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- आधिकारिक सूचना के अनुसार नोएडा के सेक्टर 16(A) फिल्मसिटी के निकट ही डीएनडी एक्सप्रेसवे की हरित पट्टी में यह वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगामी 2 माह के अंदर स्थापित एवं संचालित किया जाएगा।
- इस वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर (एपीसीटी) का आधार लगभग 4.50 मीटर व्यास वाला तथा ऊँचाई लगभग 20 मीटर होगी।
- वर्तमान समय में यह टॉवर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार संयंत्र में तैयार किया जा रहा है तथा इसे स्थापित करने के लिये अस्थायी तौर पर प्राधिकरण द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर स्थल उपलब्ध कराया गया है।
- इस टॉवर के स्थापित होने से लगभग एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तथा डीएनडी व ग्रेटर नोएडा-नोएडा एक्सप्रेसवे की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
- इस टॉवर के संचालन में प्रतिवर्ष लगभग 37 लाख रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है, जिसका 50% भाग नोएडा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।
- इस प्रकार का एक टॉवर अगस्त 2021 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर होगा।

मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में टोरेंट गैस के सिटी गैस स्टेशन का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर के खानीपुर में टोरेंट गैस के सिटी गैस स्टेशन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के प्रथम चरण में 101 घरेलू कनेक्शन और 1 औद्योगिक कनेक्शन को पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जाएगी।
- इस अवसर पर उन्होंने 8 सीएनजी स्टेशन तथा 13 पीएसए ऑक्सीजन प्लॉन्ट का लोकार्पण किया तथा 5 महिलाओं को घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस के कनेक्शन का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि रसोई गैस सिलेंडर की तुलना में पीएनजी सस्ती है तथा इसमें 35 से 40 प्रतिशत की आर्थिक बचत भी है।
- टोरेंट गैस को गोरखपुर नगर में आगामी मार्च माह तक 10 हज़ार परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है।
- इस गैस कंपनी ने जनपद गोरखपुर के साथ-साथ जनपद कुशीनगर और संतकबीर नगर के लिये पीएनजी की आपूर्ति की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के 15 जनपदों में पीएनजी गैस आपूर्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
- केंद्र सरकार ने प्रदेश को 127 ऑक्सीजन प्लॉन्ट प्रदान किये हैं। साथ ही, टोरेंट गैस कंपनी प्रदेश में 13 ऑक्सीजन प्लॉन्ट स्थापित कर रही है।
- इस प्रकार प्रदेश में कुल 547 ऑक्सीजन प्लॉन्ट लगाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 490 ऑक्सीजन प्लॉन्ट तैयार हो चुके हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री ने पुस्तक 'सावरकर-एक भूले-बिसरे अतीत की गूंज' का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर विक्रम संपत की लिखी पुस्तक 'सावरकर-एक भूले-बिसरे अतीत की गूंज' (Savarkar: Echoes from a Forgotten Past) का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक में संपत ने अथक् परिश्रम कर दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर शोध और तथ्यपरक दस्तावेज़ों के आधार पर गंभीर अध्येता के रूप में वीर सावरकर के व्यक्तित्व व कृतित्व को प्रदर्शित करने का अभिनव प्रयास किया है।
- इस पुस्तक में वीर सावरकर की जीवनी को तथ्यों और दस्तावेज़ों के आलोक में प्रकाशित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर बहुआयामी प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी रहने के साथ-साथ पत्रकारिता, दर्शन, साहित्य, इतिहास, अस्पृश्यता निवारण, समाज सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- देश की स्वतंत्र कराने के लिये वीर सावरकर अंडमान की सेल्युलर जेल की कोठरी में वर्षों तक रहे। उन्हें दो बार आजन्म कारावास की सज़ा हुई। इस दौरान वीर सावरकर ने कभी नाखूनों को बढ़ाकर, कभी कीलों-कांटों से अथवा बर्तनों को घिस-घिस कर उनकी नोकों से कोठरी की चारों दीवारों पर साहित्यिक रचनाएँ उकेरनी आरंभ कीं।
- वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक '1857 का स्वातंत्र्य समर' में सन् 1857 की शौर्यगाथा को देश के स्वाधीनता संघर्ष का प्रथम प्रयास बताया था। इस पुस्तक ने अनेक क्रांतिकारियों और युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी थी।

वन्यजीव सप्ताह 2021 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 1 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित मालसी डियर पार्क में 17 अक्टूबर, 2021 तक आयोजित होने वाले वन्यजीव सप्ताह 2021 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड के टाइगर रिज़र्व, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, कंज़र्वेशन, रिज़र्व, चिड़ियाघर, नेचर पार्क में देश भर के समस्त 18 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इससे देश के लगभग 45 करोड़ युवा छात्रों को पर्यटन से जोड़ने में मदद मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को वनों एवं वन्यजीवों की आर्थिकी से जोड़ने के लिये सी.एम. यंगईकोप्रिन्योर स्कीम (CM Young Ecopreneur Scheme) की शुरुआत की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को ईकोप्रिन्योर बनाया जाएगा।
- सी.एम. यंगईकोप्रिन्योर स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, ईकोटूरिज़्म, वन्यजीव टूरिज़्म आधारित कौशल को उद्यम में परिवर्तित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के सात रेलवे स्टेशन होंगे ईको-स्मार्ट

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सात रेलवे स्टेशनों को ईको-स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान देने और विकसित करने के लिये नामित किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इन सात रेलवे स्टेशनों में लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर स्टेशन शामिल हैं।
- ईको-स्मार्ट रेलवे स्टेशन की पहचान हेतु रेलवे स्टेशन, ट्रैक, डिब्बों का कूड़ा मैनेजमेंट रेलवे स्टेशन के आसपास से अतिक्रमण हटाना, इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक कबाड़ का निस्तारण, पानी का उपयोग और इसकी सप्लाई, ऊर्जा बचाने के लिये एलईडी लाईट, सोलर पैनल को बढ़ावा आदि मानकों पर खरा उतरना होगा।

उत्तराखंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 3 महीने के लिये बढ़ाया

चर्चा में क्यों ?

- 4 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति और हिंसा को देखते हुए राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न असामाजिक तत्त्वों द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण एनएसए का विस्तार किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत, ज़िलाधिकारियों (डीएम) को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो 31 दिसंबर तक अपने-अपने ज़िलों में हिंसा का कारण बन सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम को इसी साल 4 जून को लागू किया था।
- ऐसा माना जाता है कि हाल ही में किसान आंदोलन, राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती आक्रामकता और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने राज्य सरकार को एनएसए का विस्तार करने के लिये प्रेरित किया।

डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति को 250 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह तथा राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति को 150 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह करने का शासनादेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति पहले 11 बच्चों को दी जाती थी, जिसे अब 100 बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र-छात्राओं का चयन कर राज्य भर से प्रतिवर्ष 475 छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
- डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृति के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के छात्र/ छात्राओं एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत छात्रावाशी एवं अछात्रावाशी छात्र/ छात्राओं को प्रदान की जाती है।
- इन दोनों छात्रवृत्तियों का संचालन विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

चर्चा में क्यों ?

- 5 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज़ादी के तीनदिवसीय अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्य के 75 ज़िलों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबियाँ सौंपीं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों की 75 सफल परियोजनाओं की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया तथा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल उद्घाटन किया।
- इससे पहले, प्रधानमंत्री ने न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और न्यू अर्बन इंडिया की थीम पर प्रदर्शित 75 हाउसिंग टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
- उन्होंने राज्य के सात शहरों के लिये 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 4,737 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने 1,537.02 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं तथा प्रधानमंत्री अमृत मिशन के तहत 502.24 करोड़ रुपए की 17 पेयजल परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया और 1,256.22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 30 विकास परियोजनाओं एवं 1,441.70 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

उत्तर प्रदेश में निर्मित 'वेबली स्कॉट' बाज़ार में हुआ लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

- 7 अक्टूबर, 2021 को प्रसिद्ध ब्रिटिश आग्नेयास्त्र कंपनी वेबली और स्कॉट की घरेलू रिवॉल्वर ने लखनऊ में अपनी पहली डिलीवरी के साथ भारतीय बाज़ार में धूम मचा दी।

प्रमुख बिंदु

- कैपिटल गन हाउस के जेपीएस सियाल ने बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेड इन इंडिया' अभियान के तहत निजी क्षेत्र में बनाई गई पहली रिवॉल्वर है। पहली रिवॉल्वर सुधीर कुमार गुप्ता को सौंपी गई।
- ब्रिटिश फर्म ने आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिये लखनऊ स्थित सियाल निर्माताओं के साथ समझौता किया था और इसका निर्माण हरदोई में किया जा रहा है। समझौते के मुताबिक कंपनी रिवॉल्वर को सीधे नहीं, बल्कि गन हाउस के ज़रिये बेचेगी।
- यह इकाई देश में वेबले और स्कॉट की पहली इकाई है। इस यूनिट में रिवॉल्वर, पिस्तौल, एयरगन बनाए जाएंगे। रिवॉल्वर की कीमत करीब 1.55 लाख रुपए होगी।
- उल्लेखनीय है कि वेबले ब्रिटिश साम्राज्य की सेना, विशेष रूप से ब्रिटिश सेना को 1887 से दोनों विश्व युद्धों के दौरान आपूर्ति की गई रिवॉल्वर और स्वचालित पिस्तौल के लिये प्रसिद्ध है।
- 2010 में वेबले और स्कॉट ने व्यावसायिक बिक्री के लिये शॉटगन के उत्पादन को फिर से शुरू किया है।

उत्तराखंड में क्षेत्रीय उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 8 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने फिक्की और उत्तराखंड राज्य सरकार के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक क्षेत्रीय उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर उत्तराखंड में देहरादून के लॉजी ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया और नए उड़ान मार्गों को हरी झंडी दिखाई गई।
- 325 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ विकसित नया टर्मिनल भवन 28,729 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह व्यस्त समय के दौरान 1,200 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिसमें इस हवाई अड्डे की क्षमता आठ गुना बढ़ जाएगी।

नोट :

- इस मौके पर देहरादून-हल्द्वानी-पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर-हल्द्वानी-देहरादून सेक्टर और चिन्यालीसैण-सहस्त्रधारा-चिन्यालीसैण सेक्टर के लिये हेलीकॉप्टर सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर सेवा क्रमश: पवन हंस और हेरिटेज एविएशन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- उत्तराखंड क्षेत्र में हेली मार्गों का उद्घाटन देश में पहाड़ी क्षेत्रों की हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना के उद्देश्य के अनुरूप है। राज्य के भीतर निर्बाध हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये उत्तराखंड में 13 और हेलीकॉप्टर्स की पहचान की गई है।
- इस अवसर पर उड्डयन सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के साथ उत्तराखंड सरकार और पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन-2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया।
- इस वर्ष की थीम 'इंडिया@75: भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना' है।

उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 8 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह ने देहरादून में 'दून ड्रोन मेला 2021' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान ड्रोन और एयरोस्पोर्ट्स प्रदर्शन किये गए। इनमें सीमा सुरक्षा बल द्वार पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर्ष सचान द्वारा पैरामोटर प्रदर्शन और आईओटेकवर्ल्ड एविएशन और दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़काव संबंधी ड्रोन प्रदर्शन शामिल थे।
- इसके अलावा इस कार्यक्रम में ड्रोन एप्लिकेशन एंड रिसर्च सेंटर (डीएआरसी) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) द्वारा स्वदेशी रूप से 3 डी-प्रिंटेट ड्रोन के साथ एक आपातकालीन खोज और प्रतिक्रिया ड्रोन प्रदर्शन भी शामिल था।
- इसके बाद स्वामित्व योजना के तहत आरव अनमैंड सिस्टम (एयूएस) द्वारा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ड्रोन प्रदर्शन के साथ-साथ स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती (सेवानिवृत्त) द्वारा एक प्रशिक्षण ड्रोन का प्रदर्शन किया गया।

प्रदेश के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 8 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड की महिला अधिकारिता और बाल विकास (WECD) मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के झाझरा में राज्य के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और 'डिजिटल इंडिया मिशन' के तहत यह 'डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र' शुरू किया गया है और राज्य भर में अधिक केंद्रों को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाएगा।
- शुरुआती चरण में सरकार ने देहरादून के झजरा और विकासनगर में दो डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किये हैं।
- आर्य के अनुसार, राज्य सरकार ने देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की है, विभाग का लक्ष्य सभी जिलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल केंद्रों में विकसित करना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके लिये जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- उन्होंने यह भी बताया कि इस डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र को चलाने के लिये सॉफ्टवेयर को इस तरह से तैयार किया गया है, जिसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता आसानी से कर सकें।

नोट :

- उन्होंने कहा कि बच्चों के लिये स्मार्ट कक्षाएँ संचालित की जाएंगी और छात्रों से वर्चुअली भी जुड़ने की समुचित व्यवस्था की गई है। ऐसे केंद्रों में छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।
- डब्ल्यूईसीडी सचिव एच.सी. सेमवाल ने बताया कि इन केंद्रों के कार्यकर्त्ताओं को मुंबई के प्रशिक्षकों द्वारा केंद्रों को ठीक से संचालित करने के लिये प्रशिक्षित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से बढ़ाने के अलावा, केंद्रों को इस तरह से सजाया गया है, जो अधिक बच्चों के अनुकूल है और सीखने को बढ़ावा देता है।

जस्टिस राजेश बिंदल

चर्चा में क्यों ?

- 9 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार द्वारा जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जस्टिस बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे।
- हाल ही में जस्टिस बिंदल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़िला न्यायालयों के उपयोग हेतु आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर तैयार करने के लिये गठित की गई समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों ?

- 10 अक्टूबर, 2021 को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ताजमहल एवं आगरा किले का भ्रमण किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के पश्चात् भारत आने वाली किसी देश की पहली शासनाध्यक्ष हैं।
- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष ही भारत-डेनमार्क द्वारा 'ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप' की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
- मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल (अर्जुमन बानो) की याद में बनवाया गया ताजमहल, मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें पित्रा-दूरा शैली का प्रयोग करते हुए अलंकरण किया गया है।
- गौरतलब है कि वर्ष 1983 में आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। साथ ही यह दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है।

उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न ज़िलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 12 अक्टूबर, 2021 को रुड़की एवं देहरादून में डेंगू के नए केस सामने आए हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि डेंगू एक मच्छरजनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेवी वायरस) के कारण होती है।
- इसका प्रसार मुख्यरूप से मादा एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा होता है।
- डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके 'डेंग वैक्सिया' को अनुमोदित किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

- 13 अक्टूबर, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा 8 नवनियुक्त अपर न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 24 अगस्त को कोलेजियम द्वारा केंद्र सरकार को 13 अधिवक्ताओं एवं 4 ज़िला जजों के नाम की हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की संस्तुति की गई थी, जिनमें से 8 अधिवक्ताओं को अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- नियुक्त होने वाले अपर न्यायाधीशों में जस्टिस चंद्र कुमार राय, कृष्ण पहल, समीर जैन, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाषा विद्यार्थी, बृजराज सिंह, प्रकाश मिश्रा एवं जस्टिस विकास शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थाई वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तत्समय बढ़ा देनी चाहिये तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जो वह निर्दिष्ट करे, उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप-10 में से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में नीति आयोग द्वारा जुलाई-अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप-10 में 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों में फतेहपुर ज़िले को दूसरा, सिद्धार्थ नगर को तीसरा, सोनभद्र को चौथा एवं चित्रकूट को पाँचवा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप-10 में शामिल उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में बहराइच, श्रावस्ती एवं चंदौली शामिल हैं।
- नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई डेल्टा रैंकिंग में देश के आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रगति को दर्शाती है।
- उल्लेखनीय है कि 2018 में प्रारंभ किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य उन ज़िलों में तेजी से बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से प्रगति की है। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िलों को शामिल किया गया है।

'खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो-2021'

चर्चा में क्यों ?

- 19 अक्तूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो-2021 का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं रेशम विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 30 अक्तूबर, 2021 तक चलेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंडित दीनदयाल खादी विपणन विकास सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना एवं प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को चेक, ऋण स्वीकृति प्रमाण-पत्र एवं राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये। साथ ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार भी वितरित किये।
- इसके पूर्व उन्होंने सोलर चरखे, विद्युतचालित चाक, दोना-पत्तल निर्माण मशीनें एवं माटी कला बोर्ड के लाभार्थियों को टूलकिट वितरित किये।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 307 खादी संस्थाओं के 33 करोड़ 37 लाख 62 हज़ार रुपए के दावों का भुगतान किया गया। इसमें खादी संस्थाओं में कार्यरत् 1 लाख 61 हज़ार 345 कामगारों को 9 करोड़ 52 लाख 92 हज़ार रुपए के प्रोत्साहन बोनस का भुगतान किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 136 खादी संस्थाओं को 4 करोड़ 87 लाख 35 हज़ार रुपए के दावों का भुगतान किया गया। इसमें 25,474 कामगारों को 1 करोड़ 65 लाख 70 हज़ार रुपए प्रोत्साहन बोनस का भुगतान किया गया।
- खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोज़गार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत टूलकिट्स कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत खादी उत्पादन में वृद्धि एवं खादी कामगारों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को नि:शुल्क सोलर चरखे का वितरण किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 3 वर्षों में 3,803 लाभार्थियों को नि:शुल्क टूलकिट्स तथा सोलर चरखे, विद्युतचालित कुम्हारी चाक, दोना-पत्तल मशीन एवं आधुनिक भट्ठी-पगमिल वितरित किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,501 टूलकिट्स के वितरण का लक्ष्य है।
- उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोज़गार प्रोत्साहन मशीन (पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन) तथा दोना-पत्तल कार्य में लगे परंपरागत एवं अन्य संबंधित कारीगरों को नि:शुल्क दोना-पत्तल मेकिंग मशीनों का वितरण कराया गया है।
- उत्तर प्रदेश के कुल 57 जनपदों में 3 अलग प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मैदानी क्षेत्र के 44 जनपदों में शहतूती रेशम, विंध्याचल व बुंदेलखंड के 13 जनपदों में टसर रेशम तथा यमुना के तटीय 8 जनपदों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। प्रदेश की रेशम की खपत 3 हज़ार मीट्रिक टन है, जबकि रेशम का उत्पादन 300 मीट्रिक टन है।
- रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण, कोया उत्पादन व धागाकरण हेतु केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत उत्पादन का अनुदान व नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता दी जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मिर्ज़ापुर स्थित 'लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल राजकीय प्रशिक्षण संस्थान' का निर्माण पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसी तरह वर्ष 2019 में जनपद पीलीभीत और बहराइच में एक-एक रीलिंग मशीन की स्थापना कराकर प्रदेश में ही धागाकरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 और रीलिंग मशीनों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान

चर्चा में क्यों ?

- 19 अक्तूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बस्ती में प्रदेश में संचालित होने वाले तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से शुरू किये गए इस अभियान को पहले चरण में गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के 7 जनपदों में शुरू किया गया था, दूसरे चरण में 38 जिलों में तथा तीसरे चरण में पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है।
- इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा यह अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संचारी रोगों से बचाव के उपायों के साथ-साथ ज़िला अस्पताल तथा ग्रामीण क्षेत्र में सीएचसी/पीएचसी पर इलाज की सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं।

नोट :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 19 अक्तूबर से 17 नवंबर, 2021 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 19 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2021 तक दस्तक अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा।

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 20 अक्तूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद कुशीनगर में लगभग 254 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनपद कुशीनगर में 281.45 करोड़ रुपए की लागत के राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर के शिलान्यास सहित 180.66 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास किया।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट- लखनऊ, व वाराणसी फंक्शनल थे। प्रदेश की कनेक्टिविटी भी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिये थी।
- यह प्रदेश का 9वाँ फंक्शनल एयरपोर्ट होगा, अब उत्तर प्रदेश 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ चुका है।
- कुशीनगर, अयोध्या तथा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य हो रहा है।
- कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिमोत्तर बिहार के विकास में सहायक होगा।
- कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने के साथ-साथ इसका सीधा लाभ किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक, उद्यमी आदि को मिलेगा। सबसे अधिक लाभ यहाँ के टूरिज़्म, ट्रेवल टैक्सी, होटल-रेस्टोरेंट, छोटे-छोटे बिज़नेस करने वालों को मिलेगा। साथ ही, इस क्षेत्र के युवाओं के लिये रोज़गार के नए अवसर बनेंगे।
- इस एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में 12 देशों के राजनयिकों ने हिस्सा लिया। इस एयरपोर्ट से श्रीलंका, नेपाल, जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई देशों को भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जोड़ा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि कुशीनगर विश्व के बौद्ध मतावलंबियों की आस्था एवं प्रेरणा का केंद्र है। यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है।

मुख्यमंत्री ने की पुलिस शहीदों की पोषाहार भत्ता बढ़ाने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 21 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर राज्य में पुलिसकर्मियों के आहार भत्ते में 25 प्रतिशत इजाफा करने और हर साल मोबाइल भत्ते के रूप में 2,000 रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में ड्यूटी के दौरान जान गँवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया।
- योगी आदित्यनाथ ने इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, चीफ कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिये उनके पौष्टिक आहार भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा सभी निचली रैंक के पुलिसकर्मियों को सालाना 2,000 रुपए का मोबाइल भत्ता देने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ज़िलों और इकाइयों में तैनात पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिये 15 करोड़ रुपए और उनके कल्याण के लिये 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- इसी प्रकार कार्यरत् और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों एवं आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित 1,926 दावों के निपटान के लिये 915 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 288 पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों के लिये 5 लाख रुपए से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित 403 मामलों हेतु 4813 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानों के साथ-साथ अन्य राज्यों के केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों/अर्द्धसैनिक बलों और भारतीय सेना के 527 शहीदों और मूलरूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले के आश्रितों को वित्तीय सहायता के रूप में 124.24 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

- 22 अक्तूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- कृषकों के हित में कृषि उत्पादों के निर्यात को सरल एवं सुगम बनाने के लिये नीति में विभिन्न संशोधन किये गए हैं।
- इसके तहत नीति के प्रस्तर 6.2.1, प्रस्तर 6.2.2, प्रस्तर 6.2.3.2 एवं प्रस्तर 6.2.3.3 में संशोधन किया गया है।
- उत्तर प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 प्रख्यापित है।
- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 में निर्यात क्लस्टर्स हेतु 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरंतरता को समाप्त करते हुए विकास खंड के सीमांतर्गत न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होने का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति में क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाइयों के लिये निर्यात आधारित प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने, परिवहन अनुदान दिये जाने एवं क्लस्टर सूची में संशोधन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए भुगतान समयांतर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग) की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति का गठन किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- इसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे।
- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानानुसार उत्तर प्रदेश में उत्पादित एवं प्रसंस्कृत विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मंडी शुल्क/विकास सेस के साथ-साथ प्रयोक्ता प्रभार से छूट को भी सम्मिलित किया गया है।

फैज़ाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

- 23 अक्तूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 'फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन' का नाम बदलकर 'अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन' करने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के लिये भेजा है।
- इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया था।
- उल्लेखनीय है कि 6 नवंबर, 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने फैज़ाबाद ज़िले का नाम बदलकर अयोध्या करने और ज़िले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने को मंज़ूरी दी थी।

नोट :

उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 25 अक्तूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद सिद्धार्थनगर में 2329 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों- सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर तथा जौनपुर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इन मेडिकल कॉलेजों के नाम इस प्रकार हैं- सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाज़ीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉ. सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंती बाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियांव सिंह मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई में हरदोई मेडिकल कॉलेज।
- इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से लगभग ढाई हज़ार नए बेड्स तैयार हुए हैं। साथ ही 5 हज़ार से अधिक डॉ. और पैरामेडिकल कार्यरत् होंगे।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खुल रहे हैं। इनमें से 7 में 2019 से एमबीबीएस की कक्षाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं। 9 मेडिकल कॉलेज आज शुरू हो गए हैं तथा 14 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
- इन 30 मेडिकल कॉलेजों का कार्य भारत सरकार के सहयोग और कुछ जनपदों में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से आगे बढ़ाया है।

'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 25 अक्तूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में 64 हज़ार करोड़ रुपए की 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना' का शुभारंभ तथा 5189 करोड़ रुपए लागत की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सहित देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने, महामारी से बचाव के लिये, हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाने के लिये 64 हज़ार करोड़ रुपए से 'आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन' का शुभारंभ किया।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा तथा 730
- ज़िलों में इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप होगा।

मुख्यमंत्री ने गोंडा में 1,132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

- 27 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 1,132 करोड़ रुपए लागत की 144 विकास और चिकित्सा परियोजनाओं का शुभारंभ किया तथा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2022-23 तक प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के लाभार्थियों को घरों की सांकेतिक चाबियाँ सौंपी और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा कन्या विवाह सहायता योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ भी दिया।

नोट :

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के 45 लाख रुपए से अधिक गन्ना किसानों के लिये 1.44 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया है।

उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के चार सदस्यों ने ली शपथ

चर्चा में क्यों ?

- 27 अक्तूबर, 2021 को लखनऊ के विधानभवन में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चार नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। नए पदाधिकारियों में पूर्व कॉन्ग्रेस नेता जितिन प्रसाद भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- जितिन प्रसाद के अलावा, निषाद (निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल) पार्टी के प्रमुख संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर और गोपाल अंजन भुर्जी को विधानपरिषद के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। इन चार सदस्यों को सितंबर में उत्तर प्रदेश विधायिका के उच्च सदन के लिये नामित किया गया था।
- विदित हो कि निषाद पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव डॉ. मोहम्मद अयूब के नेतृत्व वाली पीस पार्टी के साथ गठबंधन में 72 सीटों पर लड़ा था और भदोही के ज्ञानपुर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार विजय मिश्रा ने जीत हासिल की थी।
- उत्तर प्रदेश विधानपरिषद में कुल 100 सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक 48 और भाजपा के 33 सदस्य हैं। शेष सदस्य अन्य पार्टियों के हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 28 अक्तूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2021 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक 'वृक्षारोपण जनआंदोलन, 2021' का विमोचन किया। उन्होंने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित ऐप लॉन्च किया तथा प्रदेश में तीन ईको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री को वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा दुधवा टाइगर रिज़र्व के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप प्रबंधन हेतु प्राप्त पुरस्कार सौंपा गया।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु सभी विभागों के समन्वय से कार्यवाही की गई। पहले वर्ष साढ़े पाँच करोड़ वृक्ष, दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्ष, तीसरे वर्ष 22 करोड़, चौथे वर्ष 25 करोड़ से अधिक और पाँचवे वर्ष 30 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए।
- इस सम्मेलन में 3 ईको पर्यटन सर्किट को लॉन्च किया गया है। इनमें आगरा-चंबल सर्किट, वाराणसी-चंद्रकांता सर्किट तथा गोरखपुर-सोहगीबरवा सर्किट पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं। इनके माध्यम से पर्यटकों को प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होगा।

नोट :

उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 28 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति, 2021 के प्रख्यान के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के अनुसार 'मलिन बस्ती' का अभिप्राय उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा-3 के अनुसार परिभाषित स्लम से है।
- इस नीति के अंतर्गत ऐसी मलिन बस्ती मान्य होंगी, जिनमें न्यूनतम 300 व्यक्ति निवासित हों।
- नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश को राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सक्षम प्राधिकारी, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय मूल्यांकन समिति, नगरीय स्तर पर नगर निगमों हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तथा अन्य नगर निकायों हेतु ज़िला अधिकारी की अध्यक्षता में नगरस्तरीय सक्षम प्राधिकारी का गठन किया जाएगा।
- चिह्नित मलिन बस्तियों के मूल्यांकन एवं नगरस्तरीय समक्ष प्राधिकारी को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, ज़िला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की अध्यक्षता में नगरस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।
- इस नीति में शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), क्रियान्वयन संस्था, निजी विकासकर्त्ता की भूमिका एवं दायित्व के साथ परियोजना के विकास, लाभार्थियों की पात्रता तथा उनको मिलने वाले लाभ, आवंटन प्रक्रिया, अनिवार्य विकास मानदंड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन से प्राप्त किये जाने वाले अनुदान के संबंध में सुस्पष्ट प्रावधान किये गए हैं।

सोरों सुकर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित

चर्चा में क्यों ?

- 28 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज ज़िले के पवित्र सोरों सुकर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- लंबे समय से साधु-संतों और विभिन्न संगठनों की सोरों सुकर को तीर्थस्थल घोषित किये जाने की मांग को देखते हुए इसे तीर्थस्थल घोषित किया गया है।
- इस प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थल को तीर्थ के रूप में संरक्षित करने से इसके अंतर्गत आने वाले कई छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही चक्रतीर्थ, योगतीर्थ, सूर्यतीर्थ, सोमतीर्थ और सकोटकतीर्थ को भी लाभ मिलेगा।
- सोरों सुकर क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित किये जाने से स्थानीय लोगों को विकास के अलावा रोज़गार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे।
- राज्य सरकार के फैसले से तीर्थयात्रा की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और तीर्थयात्रियों के लिये बुनियादी सुविधाओं का विकास और घाटों का विकास किया जाएगा।
- सोरों सुकर क्षेत्र कासगंज के ब्रज क्षेत्र में स्थित है और विभिन्न पुराणों में इस क्षेत्र के महत्त्व का उल्लेख किया गया है। सोरों सुकर क्षेत्र को मोक्ष का तीर्थ भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोरों सुकर क्षेत्र भगवान विष्णु के तीसरे अवतार 'वराह' का निर्वाण स्थान है। सोरों सुकर क्षेत्र में कुंड (हरिपदी गंगा) वही स्थान है, जहाँ से भगवान वराह ने बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था और तब से मृत्यु के बाद राख को इस कुंड में विसर्जित किया जाता है।

नोट :

उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति, 2021

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार शीघ्र ही नई फार्मास्यूटिकल नीति लाने जा रही है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति, 2021 का मसौदा निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपए की दवाएँ एवं चिकित्सा उपकरण खरीदे जाते हैं। ऐसे में चिकित्सा सामग्री के लिये दूसरे राज्यों एवं चीन से आयात पर निर्भरता कम करने तथा उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल विनिर्माण हब बनाने के लिये नई फार्मास्यूटिकल नीति का निर्माण किया जा रहा है।
- इससे पूर्व वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति लाई गई थी, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं-
  - फार्मा कंपनियों के तकनीकी मार्गदर्शन के लिये उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना नीति में फार्मा उद्योग के विकास हेतु चिह्नित ज़िलों में नोएडा, गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर, झाँसी, गोरखपुर आदि शामिल हैं।
  - फार्मा क्षेत्र के लिये सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की सुविधा विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएँ, जैसे- इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट, ज़मीन की मुफ्त रजिस्ट्री, ऋण के लिये 50 फीसदी ब्याज अनुदान।
  - फार्मा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रोत्साहन।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के सेक्टर-28 में प्रस्तावित है।

The Vision

नोट :